आर. उन्नीकृष्णन और अन्य

बनाम

वी. के. महानुदेवन और अन्य

(2007 की सिविल अपील सं. 3468)

10 जनवरी, 2014

[टी. एस. ठाकुर और विक्रमजीत सेन, जे. जे.]

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र-

प्रतिवादी का दावा कि वह 'थंडन' जाति, एक अनुसूचित जाति का था, को उच्च न्यायालय ने KIRTADS की रिपोर्ट और राज्य वकील द्वारा दिए गए बयान पर दिनांक 25.2.1987 के आदेश द्वारा अनुमति दी-इसके बाद, की गई टिप्पणियों के आधार पर पट्टिका जाति के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा, प्रतिवादी के जाति प्रमाण पत्र की जांच की गई और सरकार ने उसे 'थंडन' जाति का नहीं, बल्कि 'एझावा' समुदाय, एक ओबीसी का घोषित किया-उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.2.1987 के फैसले को बाध्यकारी माना पार्टियों के बीच-माना गया: उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.2.1987 को पारित आदेश, जिसे अंतिम रूप मिल चुका था, ने याचिकाकर्ता की जाति की स्थिति की नई जांच की अनुमति नहीं दी थी-हालांकि उच्च न्यायालय ने उक्त कार्यवाही और राज्य सरकार द्वारा

पारित आदेश को रद्द कर दिया था। इसके अनुसरण में, हस्तक्षेप की गारंटी देने में कोई त्रुटि नहीं हुई-हालाँकि, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2007 के संदर्भ में राष्ट्रपति के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो 30.8.2007 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। 2007 और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.8.2010 कि 'एझुवास' और 'थियास' को ओबीसी के रूप में माना जाएगा, और निर्णय प्रकृति में संभावित होने के कारण, प्रतिवादी को 30.8.2007 तक दिया गया लाभ अबाधित रहेगा-प्रतिवादी को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में भविष्य में किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा, लेकिन ओबीसी उम्मीदवार के रूप में उसे स्वीकार्य किसी भी लाभ से इनकार नहीं किया जाएगा।

निर्णय की अंतिमता- उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.2.1987 को पारित आदेश, प्रतिवादी (उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता) के 'थंडन' जाति, एक अनुसूचित जाति से संबंधित होने के दावे को अनुमति देता है, इसके बाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियों के आधार पर पट्टिका जथी का मामला, प्रतिवादी के जाति प्रमाण पत्र की जांच की गई और सरकार ने उन्हें 'थंडन' अनुसूचित जाति का नहीं, बल्कि 'एझावा' जाति, एक ओबीसी घोषित करने का आदेश पारित किया-माना गया: कानून उन अदालतों द्वारा सुनाए गए बाध्यकारी न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने का समर्थन करता है जो सक्षम हैं विषय वस्तु से निपटें-

सार्वजनिक हित व्यक्तियों को एक ही तरह के मुकदमे से दो बार परेशान किए जाने के खिलाफ है-पुनर्न्याय के सिद्धांत का एकमात्र अपवाद "धोखाधड़ी" है जो निर्णय को ख़राब करता है और किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश को अमान्य कर देता है और कानून की नजर में गैर-स्थाई-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.2.1987 को अंतिम रूप मिलने के बाद, इससे निपटाए गए प्रश्न पर कोई नई या आगे की जांच शुरू नहीं की जा सकी, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियां इसके विपरीत खड़े होने के साथ नहीं।

प्रतिवादी नं. 1 ने आवेदन किया था और, 1986 के ओपी नंबर 9216 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.2.1987 के अनुसार, उसे एक जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि वह 'थंडन' था, जो एक अधिसूचित अनुसूचित जाति थी। उन्हें एसटी/एससी उम्मीदवारों के लिए एक विशेष भर्ती योजना के तहत सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, पट्टिका जाति के मामले में उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम के अनुसार जाति के नाम को 'थिय्या' से 'थंडन' में बदलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। 1976 और आदेश दिया कि 27.7.1977 के बाद ऐसे आवेदनों के आधार पर सही किए गए सभी प्रमाणपत्रों की जांच एक जांच समिति द्वारा की जानी चाहिए। नतीजतन, जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

प्रतिवादी का पक्ष भी जांच के दायरे में आया और यह पाया गया कि प्रतिवादी वास्तव में एझुवा समुदाय से था जो ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता था। अंततः, राज्य सरकार ने रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की और प्रतिवादी क्रमांक घोषित किया। 1 चूंकि थंडन समुदाय, एक अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल 'एझावा' समुदाय से संबंधित है। प्रतिवादी नं. 1 और उसके भाई (2007 के सी.ए. संख्या 3470 में प्रतिवादी) ने सरकार द्वारा पारित आदेश को क्रमशः 2003 की ओपी संख्या 5596 और 2004 की रिट याचिका संख्या 20434 में उच्च न्यायालय सी के समक्ष चुनौती दी, जिसे एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर कहा कि प्रतिवादी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला उच्च न्यायालय ने 1986 के ओपी संख्या 9216 में दिनांक 25.2.1987 के अपने निर्णय द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया था, और उक्त प्रश्न को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। जब तक यह प्रभावी था. रिट अपील और समीक्षा याचिका को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था।

तत्काल अपीलों में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थे:

(1) "क्या अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 की जाति की स्थिति को जांच के लिए फिर से खोल सकते थे, 1986 की

ओ.पी. संख्या 9216 में उच्च न्यायालय के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 'थंडन' घोषित किया गया था"; और

(2) "क्या प्रतिवादी नंबर 1 सेवा से निष्कासन के खिलाफ सुरक्षा का दावा कर सकता है और यदि हां, तो प्रतिवादी की जाति की स्थिति के लिए प्रासंगिक कानून में बदलाव का क्या प्रभाव है"।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में, प्रतिवादी (ओ.पी. में याचिकाकर्ता) ने जाति से थंडन होने का दावा किया था और, इस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष, यह बताया गया कि निदेशक, केरल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (KIRTADS) ने एक मानवशास्त्रीय अध्ययन किया था और निष्कर्ष दर्ज किया था कि प्रतिवादी थंडन समुदाय से था और वह अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने का हकदार था। अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि KIRTADS द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को हरिजन कल्याण निदेशक, त्रिवेन्द्रम (याचिका में

प्रतिवादी संख्या 3) को सूचित किया गया था और उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.2.1987 को आदेश पारित किया। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी के पक्ष में एक जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। [पैरा 13-14]

1.2. इस आलोक में आगामी जांच शुरू की गई। पट्टिका जथी के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने 27.7.1997 के बाद सही किए गए प्रमाणपत्रों की वैधता के बारे में संदेह माना था। यह घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा1986 के ओ.पी. संख्या 9216 का निपटारा करने और प्रतिवादी के पक्ष में परिणामी प्रमाण पत्र जारी करने के लगभग आठ साल बाद आई। [पैरा 14]

पट्टिका जाति संरक्षण समिति वी. राज्य एआईआर 1995 केईआर 337-संदर्भित।

1.3. 1986 के ओ.पी. संख्या 9216 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.2.1987 को अंतिम रूप दे दिया गया है, प्रश्न पर कोई नई या आगे की जांच नहीं की गई है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियों के बावजूद इसके समाधान की पहल की जा सकती है। [पैरा 14]

1.4. पट्टिका जथी के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय उन स्थितियों से संबंधित नहीं है जहां जाति प्रमाण पत्र की वैधता प्रदान करने से संबंधित मुद्दा सुरक्षित है। उक्त निर्णय से पहले का निर्णय न्यायिक कार्यवाही का विषय था और प्रभावी ढंग से और अंततः उसी में हल किया गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी पूर्ण पीठ के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था और न ही उन कार्यवाही में चुनौती के तहत उसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया था। पूर्ण पीठ को संयोगवश प्रतिवादी को जारी किए गए प्रमाण पत्र की वैधता या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता की जांच भी नहीं करनी पड़ी, जिसके अनुसार इसे जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा जारी किया गया निर्देश संभवतः अंतर-पक्षों द्वारा दिए गए निर्णय को शून्य करने का प्रभाव नहीं डाल सकता है, जो अंतिम स्थिति प्राप्त कर चुका था और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी बना हुआ था। [पैरा 14]

1.5. यह सामान्य बात है कि कानून विषय वस्तु से निपटने के लिए सक्षम अदालतों द्वारा सुनाए गए न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने का समर्थन करता है। सार्वजनिक हित व्यक्तियों को एक ही प्रकार की मुकदमेबाजी से दो बार परेशान होने के विरुद्ध है। सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा सुनाए गए निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति को हमेशा कानून के शासन का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है जो इस देश में न्याय प्रशासन का आधार है। [पैरा 15]

दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 एस.सी.आर 574 = ए.आई.आर 1961 एस.सी. 1457-पर भरोसा किया

1.6. यहां तक कि ग़लत निर्णय भी पुनर्न्याय के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह भी इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है। पुनर्न्याय के सिद्धांत का एकमात्र अपवाद "धोखाधड़ी" है जो कि निर्णय को विकृत करता है और इसे अमान्य बना देता है। क्योंकि धोखाधड़ी किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश को कानून की नजर में अमान्य और गैर-स्थायी बना देती है। [पैरा 16 और 19]

मोहनलाल गोयनका बनाम बेनॉय किशना मुखर्जी 1953 एस.सी.आर 377= एआईआर 1953 एस.सी. 65 ए.वी. पपैय्या शास्त्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 2007 (3) एस.सी.आर 603 = (2007) 4 एस.सी.सी. 221; राजू रामसिंह वसावे बनाम महेश देवराव भिवापुरकर और अन्य 2008 (12) एससीआर 992 = (2008) 9 एससीसी 54- पर भरोसा किया गया।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हेमन्त कुमार भट्टाचार्जी 1963 सप्ली. एस.सी.आर 542 = एआईआर 1966 एससी 1061; कलिंगा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ 2013 (1) एससीआर 814 = (2013) 5 एससीसी 252; मथुरा प्रसाद बनाम डोसीबाई 1970 (3) एससीआर 830 = (1970) 1 एससीसी 613 संदर्भित।

1.7. मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में पारित आदेश दिनांक 25.2.1987 में धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं है। यह आदेश आग्रह की तुलना में सरकारी वकील द्वारा उसके समक्ष किए गए प्रस्तुतीकरण पर अधिक निर्भर करता है। रिट-याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादियों) की ओर से KIRTADS द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादियों) की जाति की स्थिति की जांच की गई थी, जिसमें थंडन होने का उनका दावा उचित पाया गया था और इस तरह, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का हकदार होने पर विवाद नहीं किया गया है। KIRTADS की रिपोर्ट को हरिजन कल्याण निदेशक ने स्वीकार कर लिया था, इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसमें दर्ज निष्कर्षों पर सवाल नहीं उठाया, जब तक कि पट्टिका जाति के मामले में पूर्ण पीठ ने रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों में किए जा रहे सुधारों पर संदेह व्यक्त नहीं किया। अनुसूचित जाति का मामला होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय को आदेश पारित करने में गुमराह किया गया या धोखे से गुमराह किया गया, रिट-याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) द्वारा गुमराह करना तो दूर की बात है। [पैरा 21]

1.8. इसलिए, 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में जी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.2.1987 का आदेश, जो अंतिम रूप ले चुका था, ने रिट-याचिकाकर्ता की जाति की स्थिति की नई जांच की अनुमति नहीं दी।

जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। आगामी कार्यवाही एवं पारित आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार ने हस्तक्षेप की गारंटी देने में कोई त्रुटि नहीं की। [पैरा 21]

2.1. राष्ट्रपति के संशोधन के कारण संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2007 के संदर्भ में आदेश जो 30. 8.2007 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एझुवास और थियास, जिन्हें तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में थंडन के नाम से भी जाना जाता है, अब 30.8.2007 से अनुसूचित जाति नहीं हैं। संसद ने तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में थंडन के नाम से जाने जाने वाले एझुवास सी और थियास को अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर कर दिया है। एझुवास और थियास को भले ही थंडन कहा जाता है और उपरोक्त क्षेत्र से संबंधित हैं, वे अब अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने के हकदार नहीं होंगे और न ही आरक्षण का लाभ उन्हें स्वीकार्य होगा। [पैरा 26-27]

2.2. संशोधित कानून को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार ने आदेश क्रमांक 93/2010/एससी/एसटी द्वारा दिनांक 30.8.2010 ने निर्देश दिया कि एझुवास और थियास जो तत्कालीन कोचीन में थंडन के नाम से जाना जाता है मालाबार को सूची III में ओबीसी के रूप में माना जाएगा। यह भाग था प्रतिवादी की ओर से विवादित नहीं। क्या है महत्वपूर्ण यह है

कि विलोपन स्पष्ट रूप से संभावित प्रकृति है।इस न्यायालय द्वारा पा/घाट जी/ला में घोषित कानून थंडन सामुदायिक संरक्षण समिति का मामला हकदार सभी थंडन जिनमें एज़ुवा और भी शामिल थे दावा करने के लिए कोचीन और मालाबार क्षेत्र से थियास अनुसूचित जाति का दर्जा. वह हक लिया जा सकता है केवल उस पर विशिष्ट प्रावधानों द्वारा पूर्वव्यापी रूप से दूर प्रभाव से या आवश्यक आशय से. ऐसी कोई बात नहीं ·संशोधन में विशिष्ट प्रावधान या इरादा यह मानने के लिए कानून कि हक छीन लिया गया है पूर्वव्यापी रूप से ताकि उन लोगों पर भी प्रभाव पड़े जो पहले से ही प्रभावित थे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का लाभ मिला उम्मीदवार. किसी भी दर पर, एक एज़ुवास को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र थंडन के नाम से जाना जाता है जो कोचीन का मूल निवासी था राज्य के मालाबार क्षेत्र को वापस नहीं लिया जा सका संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 नहीं बना थंडन की दो श्रेणियों के बीच अंतर 2007 का संशोधन अधिनियम पहली बार पेश किया गया इतना अंतर. [पैरा 28]

पालघट जिला थंडन सामुदायिक संरक्षण समिति और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य 1993 (3) पूरक। एससीआर 872 = (1994) 1 एससीसी 359 -पर भरोसा।

2.3. इसके अलावा, पट्टिका जथी के मामले में निर्णय आने तक काफी समय तक भ्रम की स्थिति बनी रहने के कारण थंडन के नाम से

जाने जाने वाले एझुवास और थियास को बाहर करने का सवाल कानून और समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों दोनों के आधार पर अनुचित होगा। [पैरा 29] [376-एफ-जी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद 2000 (5) पूरक। एससीआर 65 = (2001) 1 एससीसी 4-पर निर्भर।

कविता सोलुंके बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2012 (7) एससीआर 251 = (2012) 8 एससीसी 430; संदीप सुभाष पराते बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2006 (5) सप्ल। एससीआर 282 = (2006) 7 एससीसी 501; महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय के. निमजे 2007 (1) एससीआर 960 = (2007) 14 एससीसी 481- संदर्भित।

2.4. वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रामाणिकता की कमी का कोई सबूत नहीं है। इसलिए, मिलिंद के मामले के निर्णय के तहत उपलब्ध सुरक्षा प्रतिवादी को भी स्वीकार्य हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 2007 में प्रदर्शित अभिव्यक्ति 'थंडन' की सच्ची और सही रचना पर 'थंडन' के रूप में जाने जाने वाले 'एझुवास' और 'थियास' को शामिल नहीं किया गया है और यह मानते हुए कि दोनों अलग-अलग हैं समय के सभी प्रासंगिक बिंदु, तथ्य यह है कि 2007 के संशोधन अधिनियम तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। दोनों के बीच स्पष्ट अंतर करने से संशोधन अधिनियम लागू होने की तारीख तक राज्य

की सेवा के लिए नियुक्त सभी लोग सेवा में बने रहने के हकदार होंगे। [पैरा 32] [378-एफ-जी)

2.5. केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 5.9.2012 के एक आदेश के खिलाफ दायर 2014 की सिविल अपील संख्या 259 में, उच्च न्यायालय ने उस अपील में प्रतिवादी के पक्ष में जारी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करना उचित पाया है। कानूनी तौर पर बहुत बुरा है क्योंकि जांच समिति ने उस सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया था जिस पर उस मामले में प्रतिवादी ने भरोसा किया था। प्रमाणपत्र की वैधता की कोई जांच नहीं की गई और न ही कोई आदेश पारित किया गया स्क्रूटनी कमेटी द्वारा कारणों से समर्थित। उस तर्क में कोई कानूनी दोष नहीं है, यहां तक कि कोई विकृति भी नहीं है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले पर निष्पक्ष दृष्टिकोण रखता है और किसी भी प्रकार की अवैधता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है। [पैरा 33]

2.6. हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जबकि प्रतिवादी संख्या को लाभ दिया गया है। 30.8.2007 तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में 1, पदोन्नति या अन्यथा के संदर्भ में कोई भी लाभ, जो प्रतिवादी को उक्त तिथि के बाद दिया गया हो, केवल उसके अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में माने जाने के आधार पर दिया जा सकता

है, यदि ऐसा है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस लेने की सलाह दी जाती है। प्रतिवादी नं. 1 भविष्य में निर्धारित किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा । लेकिन ओबीसी जाति के उम्मीदवार के रूप में उसे स्वीकार्य किसी भी लाभ से इनकार नहीं किया जाएगा। [पैरा 34]

मामला कानून संदर्भः

AIR 1995 Ker 337	referred to	पैरा 14
1962 SCR 574	relied on	पैरा 15
1953 SCR 377	referred to	पैरा 16
1963 Suppl. SCR 542	referred to	पैरा 17
2013 (1) SCR 814	referred to	पैरा 18
1970 (3) SCR 830	referred to	पैरा 19
2007 (3) SCR 603	relied on	पैरा 19
2008 (12) SCR 992	relied on	पैरा 20
1993 (3) Suppl. SCR 872	referred to	पैरा 23
2000 (5) Suppl. SCR 65	relied on	पैरा 29

2012 (7) SCR 251	referred to	पैरा 30
2006 (5) Suppl. SCR 282	referred to	पैरा 31
2007 (1) SCR 960	referred to	पैरा 31

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 3468/2007

केरल के एर्नाकुलम में उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. ए. सं. 410/2006 में निर्णय और आदेश दिनांकित 28.02.2006 से।

के साथ

सी. ए. सं. 3469 , 3470 2007 और 2014 का 259।

वी. गिरि, हुज़ेफा अहमदी, मालिनी पोदुवाल, बबीता संत, आर. सतीश, लिज़ मैथ्यू, एम. एफ. फिलिप, एम. टी. जॉर्ज, कविता के. टी., राजशेखर राव, निशे राजन शोंकर (टी. टी. के. दीपक और के लिए), पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, उदयादित्य बनर्जी (मंदिर विधि फर्म के लिए) उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

टी. एस. ठाकुर, जे.

1. विशेष याचिका में दी गई छुट्टी 2013 की अपील करने की अनुमति (सिविल) No.24775।

2. इन अपीलों में विचार के लिए कानून के सामान्य प्रश्न उठते हैं जिनका निपटारा इस सामान्य आदेश द्वारा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम उन प्रश्नों को तैयार करें जो निर्धारण के लिए आते हैं, विवाद की उचित सराहना के लिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3. प्रतिवादी-वी.के. महानुदेवन ने 2007 की सिविल अपील संख्या 3468 में केरल राज्य में तहसीलदार, अलाथुर को इस आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया था कि वह 'थंडन' था जो एक अधिसूचित अनुसूचित जाति थी। तहसीलदार ने जांच की और पाया कि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से नहीं था और मामले की सूचना निदेशक, अनुसूचित जाति विकास विभाग को दी, जिन्होंने मामले को केरल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डवलपमेंट स्टडीज के निदेशक को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (संक्षेप में 'किरताड्स') जांच और रिपोर्ट के लिए भेज दिया।

4. प्रमाण पत्र देने से इनकार करने से व्यथित होकर प्रतिवादी ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 1986 का ओ.पी. नंबर 9216 दायर किया, जिसे उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी, 1987 के अपने आदेश के अनुसार

संबंधित तहसीलदार को उक्त प्रतिवादी के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी करें निर्देश देते हुए निपटा दिया। तदनुसार उनके पक्ष में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह सामान्य आधार है कि प्रतिवादी को एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए एक विशेष भर्ती योजना के तहत सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था।

5. प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी होने और राज्य सेवा में एक सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में उसकी नियुक्ति के लंबे समय बाद, केरल पट्टिका जाति संरक्षण समिति बनाम राज्य एआईआर 1995 के.आर. 337 मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम , 1976 के अनुसार जाति के नाम को 'थिय्या' से 'थंडन' में बदलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे और आदेश दिया गया था कि ऐसे सभी प्रमाणपत्रों को इसके आधार पर ठीक किया जाए। 27 जुलाई 1977 के बाद के आवेदनों की जांच एक जांच समिति द्वारा की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा:

> "...1976 के आदेश में थंडन समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के तुरंत बाद एक ही कारण का आरोप लगाते हुए एझावा/थिय्या से थंडन तक जाति के नाम में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल करने

पर प्रथम दृष्टया विचार किया जा सकता है। जैसा कि पहले प्रतिवादी के जवाबी हलफनामे में आरोप लगाया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है, अनुसूचित जाति के लाभों का लाभ उठाने के लिए एझावा/थियास के वर्ग की ओर से एक ठोस प्रयास के रूप में इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में थंडन था और अनुसूचित जाति का था, तो उसकी जाति स्कूल के रिकॉर्ड में एझावा या थिय्या के रूप में दर्ज की गई होती। इस बात पर भी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता कि बड़ी संख्या में मामलों में बिना किसी कारण के एक ही प्रकार की गलती को तब तक रिकॉर्ड में रहने दिया गया जब तक कि थंडन समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं कर लिया गया। इस प्रकार पूरी समस्या पर गंभीरता से विचार करते हुए हम यह मानेंगे कि उन सभी मामलों में जहां 27-7-1977 को और उसके बाद प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, 1976 के आदेश की तारीख में जाति के नाम को एझावा/थिय्या से थंडन तक सही किया गया है और अन्य मामले जहां जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में बदलने के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, ऐसे जारी किए गए प्रमाण पत्र वैध रूप से

संदिग्ध घोषित किए जा सकते हैं, जब तक कि हमारे द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार पहले प्रतिवादी द्वारा गठित की जाने वाली जांच समिति द्वारा उनकी जांच नहीं की जाती है। उस संबंध में..." (जोर दिया गया)

6. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रतिवादी के पक्ष में जारी जाति प्रमाण पत्र भी जांच के दायरे में आया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि KIRTADS द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 की अनुमति देते समय उच्च न्यायालय द्वारा जिस पर भरोसा किया गया था, वह गलत थी और प्रतिवादी वास्तव में एझुवा समुदाय से था जो ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता था। निदेशक, KIRTADS ने तदनुसार प्रतिवादी को इस दावे के समर्थन में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया कि वह थंडन है और इसलिए अनुसूचित जाति का है। उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर प्रतिवादी ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 1991 का ओ.पी. नंबर 5834 दायर किया जिसमें उसने अपनी जाति की स्थिति से संबंधित प्रस्तावित जांच कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि पालघाट जिला थंडन सामुदायिक संरक्षण समिति में इस न्यायालय का निर्णय और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य । (1994) 1 एस.सी.सी. 359 ने पालघाट जिले में एझुवा/थिय्या के 'थांडन' होने से संबंधित विवाद को सुलझा लिया था। यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का स्वयं का मामला कि वह थंडन

अनुसूचित जाति का था, उच्च न्यायालय द्वारा 1986 के ओपी नंबर 9216 में पारित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया था। इन तर्कों को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 15 दिसंबर, 1998 द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर ओ.पी. संख्या 5834/1991 को अनुमति दी और चल रही जांच कार्यवाही को रद्द कर दिया।

7. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर केरल राज्य ने 1999 की रिट अपील संख्या 1300 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 14 जून, 1999 के अपने फैसले और आदेश द्वारा अनुमति दे दी और KIRTADS द्वारा प्रतिवादी की जाति स्थिति की नए सिरे से जांच का निर्देश दिया। प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका संख्या 236/1999 को डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 29 जुलाई 1999 द्वारा खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने, हालांकि, विशेष रूप से प्रतिवादी के लिए ओ.पी. नंबर में सुनाए गए निर्णयों को लाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी। 1986 का 9216 और 1988 का ओ.पी. नंबर 5470, निदेशक KIRTADS के नोटिस में और उक्त निर्णयों के प्रभाव के बारे में अपनी कोई भी राय व्यक्त करने से इनकार कर दिया। यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निम्नलिखित अंश से स्पष्ट है:

> "बहस के समय हमारा ध्यान एक्सटेंशन की ओर आकर्षित हुआ। ओ.पी. 9216/86 में पी7 निर्णय दिनांक 25.2.87

और ओ.पी. 5470/88 में इस न्यायालय के एक डिवीजन का निर्णय भी इस प्रस्ताव के लिए कि इस न्यायालय ने उपरोक्त दो मामलों में याचिकाकर्ता की स्थिति को पहले ही स्वीकार कर लिया है। हम ऊपर उल्लिखित दोनों निर्णयों पर कोई राय व्यक्त करने के इच्छुक नहीं हैं। यह समीक्षा याचिकाकर्ता पर निर्भर है कि वह उपरोक्त दो निर्णयों और अन्य सामग्रियों, यदि कोई हो, को अपने विचार और रिपोर्ट के लिए निदेशक के समक्ष रखें। KIRTADS निदेशक को निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया जाता है और सरकार पूरे मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती है और तदनुसार उचित आदेश पारित कर सकती है। समीक्षा याचिका का निपटारा उपरोक्तानुसार किया जाता है।"

8. तदनुसार एक नई जांच शुरू हुई जिसमें सतर्कता अधिकारी, KIRTADS ने बताया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध वंशावली और दस्तावेजी साक्ष्य बिना किसी संदेह के साबित हुए कि प्रतिवादी और उसके सभी सजातीय और रिश्तेदार 'एझुवा' के थे, न कि 'थंडन' समुदाय के। उक्त रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जांच समिति ने प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उसके पक्ष में जारी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाए।

9. उसे जारी किए गए नोटिस से व्यथित होकर प्रतिवादी ने एक बार फिर 2000 के ओ.पी. नंबर 2912 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2001 द्वारा इस निर्देश के साथ निपटाया कि उचित आदेशों के लिए राज्य सरकार के समक्ष KIRTADS रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्य सरकार ने तदनुसार मामले पर विचार किया और 18 जनवरी, 2003 को एक आदेश पारित किया, जिसके द्वारा वह रिपोर्ट और KIRTADS द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हुई और निम्नानुसार घोषित की गई:-

> "(i) यह घोषित किया जाता है कि श्री. वी.के. महानुदेवन पुत्र श्री कुंजुकुट्टन, कुन्निसेरी हाउस, कोट्टापराम्बिल, वडक्कनचेरी, अलाथुर, जिला पलक्कड़ जो अब कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचाई प्रभाग, सिंचाई विभाग, पलक्कड़ के रूप में कार्यरत हैं, थंडन समुदाय से संबंधित नहीं हैं जो एक अनुसूचित जनजाति है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल एझावा समुदाय से संबंधित है।
>
> (ii) उसके परिवार का कोई भी सदस्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए अपेक्षित किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। यदि श्री वी.के. महानुदेवन के

परिवार के किसी भी सदस्य ने अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए निर्धारित किसी भी लाभ का लाभ उठाया है तो लिए गए ऐसे सभी लाभ वसूल किए जाएंगे।

(iii) यदि श्री वी.के. महानुदेवन के परिवार के सदस्यों के संबंध में उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज जाति प्रविष्टि थंडन (एससी) है, तो इसे एझावा के रूप में सही किया जाएगा।

(iv) इसके बाद श्री वीके महानुदेवन के परिवार के किसी भी सदस्य को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। श्री वी.के. महानुदेवन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त सभी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

(v) इस आदेश के अनुसार कार्रवाई पूरी होने पर सिंचाई विभाग में लघु सिंचाई प्रभाग के कार्यकारी अभियंता श्री वी.के. महानुदेवन की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी और श्री वी.के. महानुदेवन को सिंचाई विभाग में जिस पद पर नियुक्त किया गया था, उस पद पर अनुसूचित जाति समुदाय की नियुक्ति की जाएगी यदि उनकी नियुक्ति अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में विचाराधीन थी।"

10. सरकार द्वारा पारित आदेश से व्यथित, प्रतिवादी और उसके भाई, जो 2007 की सिविल अपील संख्या 3470 में प्रतिवादी हैं, ने सरकार द्वारा पारित आदेश को 2003 की ओ.पी. संख्या 5596 और रिट याचिका (सी) में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।) क्रमशः 2004 की संख्या 20434, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 11 नवंबर, 2005 के संदर्भ में मुख्य रूप से इस आधार पर अनुमति दी थी कि प्रतिवादी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला पहले ही निर्णय द्वारा समाप्त हो चुका था। 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी, 1987 को दिनांकित किया और कहा कि जब तक उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय प्रभावी है, तब तक उक्त प्रश्न को दोबारा नहीं खोला जा सकता है।

11. केरल राज्य ने तब 2006 की रिट अपील संख्या 134 को प्राथमिकता दी थी, जिसे उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 25 जनवरी, 2006 के संदर्भ में एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए खारिज कर दिया था कि इस मुद्दे के संबंध में प्रतिवादी की जाति की स्थिति अंतर पक्षों द्वारा पारित न्यायिक आदेश द्वारा तय की गई थी और इसलिए, इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता था। सिंचाई विभाग के पीड़ित सदस्यों द्वारा दायर रिट अपील संख्या 2006 की 410 और प्रतिवादी के संबंध में राज्य द्वारा दायर 2006 की रिट अपील संख्या 193 को डिवीजन बेंच ने क्रमशः 28 और 27 जनवरी 2006

के आदेश द्वारा समान शर्तों पर खारिज कर दिया था। इसलिए डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर 2006 की समीक्षा याचिका संख्या 263 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि 1986 के ओ.पी. संख्या 9216 में फैसले ने प्रतिवादी की जाति की स्थिति के संबंध में प्रश्न को प्रभावी ढंग से सुलझा लिया था। उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा 2007 की सिविल अपील संख्या 3469 और 3470 दायर की गई है, जबकि 2007 की सिविल अपील संख्या 3468 केरल सरकार के सिंचाई विभाग के सदस्यों द्वारा दायर की गई है। अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका (सिविल) संख्या 2013 की 24775 से उत्पन्न सिविल अपील राज्य द्वारा 5 सितंबर, 2012 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

12. इन अपीलों में दो अलग-अलग प्रश्न निर्धारण के लिए आते हैं। पहला यह है कि क्या अपीलकर्ता प्रतिवादी-वी.के. महानुदेवन की जाति की स्थिति को फिर से जांच के लिए खोल सकते थे, भले ही 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में उच्च न्यायालय के फैसले ने उन्हें अनुसूचित जाति से संबंधित 'थंडन' समुदाय घोषित कर दिया हो। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि 1986 के O.P. No.9216 में उसके निर्णय और आदेश ने प्रतिवादी की जाति की स्थिति के संबंध में प्रश्न को प्रभावी ढंग से सुलझाया था जिसे फिर से नहीं खोला जा सकता था क्योंकि उक्त निर्णय अंतिम रूप ले चुका था। दूसरा और एकमात्र अन्य

प्रश्न जो निर्धारण के लिए उठेगा वह यह है कि क्या प्रतिवादी-वी.के. महानुदेवन सेवा से निष्कासन के खिलाफ सुरक्षा का दावा कर सकते हैं और यदि हां, तो प्रतिवादी की जाति की स्थिति के लिए प्रासंगिक कानून में बदलाव का क्या प्रभाव होगा। हम क्रमशः दो प्रश्नों से निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

13. 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में प्रतिवादी (ओ.पी. में रिट याचिकाकर्ताओं) ने दावा किया था कि वह जाति से थंडन हैं, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम , 1976 के संदर्भ में एक अनुसूचित जाति है। एस.एल.सी.सी. पुस्तक में प्रतिवादी को "थंडन हिंदू" के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन वह ओबीसी श्रेणी में आता था। उन्होंने ओबीसी के रूप में अपना विवरण हटाकर और उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में मानने के लिए एस.एल.सी.सी. पुस्तक में सुधार के लिए आवेदन किया। चूंकि सुधार जल्दी नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उत्तरदाताओं के खिलाफ उन्हें अनुसूचित जाति का मानने और संबंधित रिकॉर्ड में उचित प्रविष्टियां करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में केरल लोक सेवा आयोग, निदेशक, हरिजन कल्याण बोर्ड, त्रिवेन्द्रम सहित अन्य लोग शामिल थे। जब मामला सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष पेश हुआ, तो यह बताया गया कि केरल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स

एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कोझिकोड (KIRTADS) के निदेशक ने एक मानवशास्त्रीय अध्ययन किया था और एक निष्कर्ष दर्ज किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता थंडन समुदाय से था और वह अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने का हकदार था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि KIRTADS द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को हरिजन कल्याण निदेशक, त्रिवेन्द्रम-रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 को सूचित किया गया था और उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष की गई इन दलीलों पर ही उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 25 फरवरी, 1987 को एक आदेश पारित किया, जिसका ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:-

> "मैं सरकारी वकील की दलील दर्ज करता हूं कि तीसरे प्रतिवादी ने चौथे प्रतिवादी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है कि याचिकाकर्ता थंडन है और इसलिए अनुसूचित जाति के रूप में लाभ का हकदार है। छठा प्रतिवादी इस निष्कर्ष को लागू कर सकता है और याचिका को निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी कर सकता है जो प्रमाणित करता है कि याचिकाकर्ता थंडन, अनुसूचित जाति का सदस्य है। यह आज से दस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। इसके आधार पर 5 वां प्रतिवादी भी याचिकाकर्ता की

एस.एस.एल.सी. पुस्तक में उसे अनुसूचित जाति का मानते हुए आवश्यक बदलाव करेगा, न कि डीबीसी का। यह भी 5 वें प्रतिवादी द्वारा आज से एक महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।"

14. उपरोक्त परिस्थितियों में जाति प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी के पक्ष में जारी किया गया था, जिस आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, उसे आज तक किसी भी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई है, अकेले संशोधित किया गया है या रद्द नहीं किया गया है। उपरोक्त संदर्भ में प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा प्रतिवादी की जाति स्थिति की नई जांच शुरू की जा सकती है। जैसा कि पहले देखा गया था, केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा केरल पट्टिका जाति संरक्षण समिति बनाम राज्य ए.आई.आर. 1995 केर 337 मामले में की गई कुछ टिप्पणियों के आलोक में शुरू की गई थी, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने वैधता के बारे में संदेह माना था। प्रमाण पत्र जो 27 जुलाई, 1997 के बाद सही किए गए थे। यह घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 का निपटारा करने और प्रतिवादी के पक्ष में परिणामी प्रमाण पत्र जारी करने के लगभग 8 साल बाद आई। उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री गिरि द्वारा सही तर्क दिया गया था कि 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अंतिम रूप देने के बाद तय किए गए प्रश्न पर कोई

नई या आगे की जांच शुरू नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियों के बावजूद इसके विपरीत। पट्टिका जाति के मामले (सुप्रा) में उच्च न्यायालय का निर्णय, इसे पढ़ने से स्पष्ट है, उन स्थितियों से निपटता नहीं है जहां उक्त निर्णय से पहले प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की वैधता प्रदान करने का मुद्दा विषय था। न्यायिक कार्यवाही और प्रभावी ढंग से और अंततः उसी में हल किया गया। इसके अलावा, प्रतिवादी पूर्ण पीठ के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था और न ही उन कार्यवाही में चुनौती के तहत उसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया था। पूर्ण पीठ को संयोगवश प्रतिवादी को जारी किए गए प्रमाण पत्र की वैधता या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता की जांच भी नहीं करनी पड़ी, जिसके अनुसार इसे जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा जारी किया गया निर्देश संभवतः अंतर-पक्षीय निर्णय को शून्य करने का प्रभाव नहीं डाल सकता है, जो अंतिम स्थिति प्राप्त कर चुका था और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी बना हुआ था।

15. यह सही है कि कानून उन न्यायालयों द्वारा सुनाए गए बाध्यकारी न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने का समर्थन करता है जो विषय वस्तु से निपटने में सक्षम हैं। सार्वजनिक हित व्यक्तियों को एक ही प्रकार की मुकदमेबाजी से दो बार परेशान होने के विरुद्ध है। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा सुनाए गए निर्णयों के बाध्यकारी चरित्र को हमेशा कानून के शासन का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है जो इस

देश में न्याय प्रशासन का आधार है। हम दरियाव बनाम यू.पी. राज्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का लाभ उठा सकते हैं । ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1457 जहां न्यायालय ने कानून को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया:

> "यह बड़े पैमाने पर जनता के हित में है कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा सुनाए गए बाध्यकारी निर्णयों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, और यह भी सार्वजनिक हित में है कि व्यक्तियों को एक ही तरह की मुकदमेबाजी से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए। (***) सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा सुनाए गए निर्णयों का बाध्यकारी चरित्र स्वयं कानून के शासन का एक अनिवार्य हिस्सा है, और कानून का शासन स्पष्ट रूप से न्याय प्रशासन का आधार है जिस पर संविधान इतना जोर देता है।"

16. यह कि गलत निर्णय भी पुनर्न्याय के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह भी इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है। मोहनलाल गोयनका बनाम बेनॉय किशन मुखर्जी ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 65 में, इस न्यायालय ने कहा:

"इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है कि कानून के प्रश्न पर एक गलत निर्णय भी संबंधित पक्षों के बीच 'न्याय निर्णय' के रूप में कार्य करता है। किसी न्यायिक निर्णय के सही या अन्यथा होने का इस सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है कि यह 'रेस ज्यूडिकाटा' के रूप में कार्य करता है या नहीं।"

17. इसी प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हेमन्त कुमार भट्टाचार्जी AIR 1966 SC 1061 में, इस न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:

"न्यायालय द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय दोनों पक्षों के बीच उतना ही बाध्यकारी होता है जितना कि एक सही निर्णय और इसे केवल उच्च न्यायाधिकरणों में अपील या कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली समीक्षा जैसी अन्य प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।"

18. कलिंगा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (2013) 5 एस.सी.सी. 252 में इस न्यायालय का हालिया निर्णय उसी सिद्धांत की समय पर याद दिलाता है। इस संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेद उपयुक्त है:

"हमारी राय में, यदि पार्टियों को उन मुद्दों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी जाती है जो कानून में बाद के बदलाव पर सक्षम क्षेत्राधिकार

की अदालत द्वारा तय किए गए हैं, तो संबंधित सभी पूर्व मुकदमे हमेशा प्रवाह की स्थिति में रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में, हर बार जब किसी कानून या उसके प्रावधान को अधिकारातीत घोषित कर दिया जाता है, तो इसका परिणाम ऐसे निर्णय की तारीख के बाद की सीमा अवधि के भीतर तय किए गए मामलों को फिर से खोलना होगा।

19. मथुरा प्रसाद बनाम डोसीबाई (1970) 1 एस.सी.सी. 613 में, इस न्यायालय ने माना कि पुनर्न्याय के नियम के आवेदन के लिए, न्यायालय को पहले के फैसले की शुद्धता या अन्यथा से कोई सरोकार नहीं है। यदि कोई मामला किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पिछली कार्यवाही में पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से तय किया गया है, तो उसे उसी पक्षों के बीच किसी भी बाद के मुकदमे में अंतिम निर्णय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है। यह समान पक्षों के बीच पहले की कार्यवाही में निर्धारित कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्नों के संबंध में भी सच है, जिन्हें समान पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में संशोधित या फिर से खोला नहीं जा सकता है। यह कहने के बाद, हमें यह जोड़ना होगा कि पुनर्न्याय के सिद्धांत का एकमात्र अपवाद "धोखाधड़ी" है जो निर्णय को दूषित करता है और इसे अमान्य बना देता है। इस न्यायालय ने एक से अधिक निर्णयों में माना है कि धोखाधड़ी किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश को कानून की नजर में अमान्य और गैर-स्थायी बना देती है। ए.वी. पपैय्या शास्त्री बनाम ए.पी. सरकार , (2007) 4 एस.सी.सी. 221 में,

धोखाधड़ी को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया था:

> "धोखाधड़ी को दूसरे का अनुचित लाभ उठाकर कुछ अनुचित या अवांछनीय लाभ हासिल करने के उद्देश्य से जानबूझकर किए गए धोखे के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। धोखाधड़ी में एक को दूसरे की हानि और कीमत पर लाभ मिलता है। यहां तक कि अधिकांश गंभीर कार्यवाहियां भी तब दूषित हो जाती हैं यदि वे धोखाधड़ी से की गई हों। इस प्रकार धोखाधड़ी एक बाहरी संपार्श्विक कार्य है जो सभी न्यायिक कृत्यों को दूषित कर देता है, चाहे वह रेम में हो या व्यक्तिगत रूप में। "मुकदमे की अंतिमता" के सिद्धांत को बेतुकेपन की हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि इसे बेईमान और धोखेबाज वादियों द्वारा उत्पीड़न के इंजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

20. इसी आशय का निर्णय राजू रामसिंह वासवे बनाम महेश देवराव भिवापुरकर और अन्य , (2008) 9 एस.सी.सी. 54 में दिया गया है, जहां इस न्यायालय ने कहा था:

"यदि अदालत में कोई धोखाधड़ी की गई है, तो उसके आधार पर या अन्यथा किसी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।"

21. वर्तमान मामले में हमें 1986 के ओ.पी.नंबर 9216 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं दिखता है। यह आदेश स्पष्ट रूप से पढ़ने से स्पष्ट है कि यह उसके समक्ष सरकारी वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर अधिक निर्भर करता है। रिट-याचिकाकर्ताओं (यहाँ उत्तरदाताओं) की ओर से आग्रह किए गए लोगों की तुलना में KIRTADS द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं (यहां प्रतिवादियों) की जाति की स्थिति की जांच की गई थी, जिसमें थंडन होने का उनका दावा उचित पाया गया था, इसलिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का हकदार होने पर विवाद नहीं किया गया है। इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि KIRTADS की रिपोर्ट को हरिजन कल्याण निदेशक, त्रिवेन्द्रम ने स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसमें दर्ज निष्कर्षों पर सवाल नहीं उठाया, जब तक कि पट्टिका जाति के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने रिकॉर्ड में किए गए सुधारों के बारे में संदेह व्यक्त नहीं किया और अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए प्रमाण पत्र। ऐसा होने पर, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय को आदेश पारित करने के लिए गुमराह किया गया या धोखे से गुमराह किया गया,

रिट-याचिकाकर्ताओं (यहाँ प्रतिवादी) द्वारा गुमराह करना तो दूर की बात है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि KIRTADS द्वारा किया गया मानवशास्त्रीय अध्ययन थंडन को प्रतिवादी की तरह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित मानने के लिए एक ठोस आधार प्रदान नहीं कर सकता है, जो प्रमाण पत्र की शुद्धता के संबंध में मुद्दा है और ऐसे मामले की नए सिरे से जांच विचारार्थ सामने आई। भले ही कोई यह मान ले कि KIRTADS द्वारा निकाला गया निष्कर्ष किसी भी कारण से पूरी तरह से सटीक और विश्वसनीय नहीं था, यह दिखाने के लिए किसी अन्य सामग्री के अभाव में ऐसा नहीं होगा कि ऐसा निष्कर्ष और जांच पूरी तरह से अप्रासंगिक या पर आधारित एक दिखावा था। अस्वीकार्य सामग्री और असंगत विचारों से प्रेरित होकर अपने आप में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा तय की गई बातों को अस्थिर करने का आधार प्रदान किया गया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि 1986 की ओ.पी. संख्या 9216 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश धोखाधड़ी के आधार पर अमान्य था, जिसने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हमें प्रभावित नहीं किया है। इसलिए, उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा 1986 के ओ.पी. नंबर 9216 में पारित आदेश, जो अंतिम रूप ले चुका था, ने रिट-याचिकाकर्ता की जाति की स्थिति की नई जांच की अनुमति नहीं दी। हालाँकि उच्च न्यायालय ने उक्त कार्यवाही और उसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा

पारित आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता में कोई त्रुटि नहीं हुई।

22. यह हमें दूसरे प्रश्न पर लाता है जिसका उत्तर केवल उसी परिप्रेक्ष्य में दिया जा सकता है जिसमें यह विचार के लिए उठता है। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में उन जातियों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें देश के विभिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है। भाग XVI तत्कालीन त्रावणकोर और कोचीन राज्य से संबंधित है। उस भाग के आइटम 22 में पूरे राज्य के प्रयोजनों के लिए "थंडन" को एक अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। राष्ट्रपति के आदेश को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित किया गया था। केरल राज्य (त्रिवेंद्रम, कोच्चि राज्य के उत्तराधिकारी) पर लागू भाग V वाली सूची में, एक जाति के रूप में 'थंडन' दिखाई दिया। मालाबार जिले को छोड़कर पूरे राज्य के प्रयोजनों के लिए मद 14 पर। फिर 27 जुलाई, 1997 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम , 1976 आया। केरल राज्य पर लागू भाग VII के तहत पहली अनुसूची में 'थंडन' को एक जाति के रूप में आइटम में दिखाया गया था।

61. उक्त भाग में दिखाई गई दो अन्य जातियों अर्थात् बोयन और मलायन के विपरीत, जिन्हें केरल राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुसूचित

जाति के रूप में दिखाया गया था, थंडन की ऐसी कोई भौगोलिक या क्षेत्रीय सीमा नहीं थी। इसका तात्पर्य यह था कि 'थंडन' को पूरे केरल राज्य के लिए अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया था।

23. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम , 1976 की घोषणा के परिणामस्वरूप, केरल राज्य सरकार को यह आरोप लगाते हुए शिकायतें मिलनी शुरू हो गई कि 'थंडन' अनुसूचित जाति के आरक्षण का नाजायज फायदा उठा रहे थे। मालाबार क्षेत्रों के एझुवा/थिय्या समुदाय के एक वर्ग और मालाबार जिलों के कुछ तालुकों को भी बुलाया गया था । शिकायतों में सुझाव दिया गया कि थंडन की ये दो श्रेणियां एक-दूसरे से काफी अलग और विशिष्ट थीं और आम तौर पर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित थंडन को मिलने वाले लाभ को एझुवा/थिय्या समुदाय से संबंधित लोगों को लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति नहीं. इन रिपोर्टों और शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि मालाबार क्षेत्रों के सभी चार जिलों और त्रिचूर जिले के थलापिल्ली, वडक्कनचेरी और चावक्का के तालुकों के 'थांडन' को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या आवेदक अनुसूचित जाति के थंडन समुदाय से है या एझुवा/थिय्या समुदाय के थंडन समुदाय से है और 'थंडन' जो अनुसूचित जाति के थे, उन्हें सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करते समय

अधिकारियों को समुदाय का नाम नोट करना चाहिए। प्रमाणपत्र में "एझुवा/थिय्या के अलावा अन्य थंडन" लिखा है। वर्ष 1987 में पारित एक अन्य आदेश का पालन करने के लिए इन निर्देशों को वापस ले लिया गया, जिसके द्वारा सरकार ने एक बार फिर निर्देश दिया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय, राजस्व प्राधिकरण को यह पता लगाने के लिए उचित सत्यापन करना चाहिए कि क्या संबंधित व्यक्ति थंडन जाति का है, न कि एझुवा/थिय्या का। अंततः मामला पालघाट जिला थंडन सामुदायिक संरक्षण समिति और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (1994) 1 एस.सी.सी. 359 इस न्यायालय तक पहुंच गया। जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में विचार के लिए मुख्य प्रश्न तैयार किया:

"इन रिट याचिकाओं और अपीलों में जो प्रमुख प्रश्न उठता है, वह केरल राज्य के उस निर्णय की वैधता के संबंध में है, जिसमें राज्य के वर्तमान पालघाट जिले सहित तत्कालीन मालाबार जिले के थंडन समुदाय के सदस्यों के साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। केरल के अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में।

24. इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति की समीक्षा की और घोषणा की कि थंडन समुदाय को अनुसूचित जाति के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है, जैसा कि तब था, यह राज्य सरकार या यहां तक कि इस अदालत के लिए भी खुला नहीं था कि वह यह निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करे

कि क्या कोई वर्ग एझुवा/थिय्या जिसे राज्य के मालाबार क्षेत्र में थंडन कहा जाता था, को अनुसूचित जाति के लाभ से बाहर रखा गया था। इस न्यायालय ने कहा:

अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को न केवल उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है जिन्हें किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा, बल्कि "जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों" को भी निर्दिष्ट करने का अधिकार है, जिन्हें अनुसूचित जाति माना जाएगा। किसी राज्य के संबंध में अनुच्छेद 341 के कारण किसी जाति, नस्ल या जनजाति का कोई भाग या समूह या खंड, जो समग्र रूप से अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं है, को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसलिए, यह मानते हुए कि एझावा/थिय्या समुदाय (जिसे अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है) का एक वर्ग है, जिसे मालाबार क्षेत्र के कुछ हिस्सों में थंडन कहा जाता है, वह वर्ग भी अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने का हकदार है। अनुसूचित जाति आदेश के प्रावधानों के कारण पूरे राज्य में थंडनों को अनुसूचित जाति माना जाता है, जैसा कि अब है। एक बार जब पूरे राज्य में थंडन अनुसूचित जाति आदेश के कारण अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने के हकदार हो जाते हैं, जैसा कि अब है, राज्य सरकार के लिए अन्यथा कहने का अधिकार नहीं है, जैसा कि 1987 के आदेश में कहा गया है। (जोर दिया गया)

25. उपरोक्त से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि थंडन, चाहे वे मालाबार क्षेत्र से संबंधित एझुवा/थिय्या थे, जिन्हें थंडन के रूप में जाना जाता है, इस न्यायालय की उपरोक्त घोषणा के कारण राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने के लाभ के हकदार थे, आदेश दें। उनके थंडन होने की कोई भी जांच, जो अनुसूचित जाति के थे, इस न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अस्वीकार्य के रूप में निषिद्ध है। राज्य सरकार ने एक ओर प्रतिवादी की तरह थंडन के रूप में जाने जाने वाले एझुवा/थिय्या और दूसरी ओर अनुसूचित जाति श्रेणी में आने वाले थंडन के बीच जो अंतर करना चाहा, वह उपरोक्त घोषणा के कारण समाप्त हो गया। प्रतिवादी के खिलाफ ऐसा कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है, खासकर जब अपीलकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि प्रतिवादी केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र से एझुवा नहीं है।

26. पट्टिका जाति के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के बाद से कानूनी स्थिति में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम , 2007 के संदर्भ में राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन के कारण बदलाव आया है, जिसे सहमति प्राप्त हुई है। 29 अगस्त, 2007 को राष्ट्रपति थे और इसे 30 अगस्त, 2007 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम ने , अन्य बातों के साथ, भाग VIII-केरल में प्रविष्टि 61 के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए:-

"61। थंडन (एझुवास और थियास को छोड़कर, जिन्हें तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में थंडन के नाम से जाना जाता है) और (बढ़ई जिन्हें पूर्व कोचीन और त्रावणकोर राज्य में थाचन के नाम से जाना जाता है)"।

27. उपरोक्त के आलोक में इसमें कोई संदेह नहीं है कि एझुवास और थियास, जिन्हें तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में थंडन के नाम से भी जाना जाता है, अब 30 अगस्त, 2007 की तारीख से उक्त राज्य के लिए अनुसूचित जाति नहीं हैं। संशोधन अधिसूचित किया गया। यह स्पष्ट है कि संसद ने तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में थंडन के नाम से जाने जाने वाले एझुवास और थियास को अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने के बारे में प्रचलित भ्रम को दूर कर दिया है। एझुवास और थियास को भले ही थंडन कहा जाता है और उपरोक्त क्षेत्र से संबंधित हैं, वे अब अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने के हकदार नहीं होंगे और न ही उन्हें आरक्षण का लाभ स्वीकार्य होगा।

28. संशोधित कानून को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार ने आदेश संख्या 93/2010/एससी/एसटी दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा निर्देश दिया है कि एझुवास और थियास, जिन्हें तत्कालीन कोचीन और मालाबार में थंडन के नाम से जाना जाता है,सूची III में ओबीसी के रूप में माना जाएगा, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील श्री गिरि ने भी इस भाग पर

कोई विवाद नहीं किया, जिन्होंने उचित रूप से स्वीकार किया कि 2007 के संशोधन अधिनियम (सुप्रा) के परिणामस्वरूप, तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में थंडन के नाम से जाने जाने वाले एझुवास और थियास को अनुसूचित जाति की सूची से हटा दिया गया है और अब राज्य सरकार द्वारा उन्हें ओबीसी के रूप में माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त क्षेत्र में थंडन के रूप में जाने जाने वाले एझुवास और थियास के लिए विलोपन स्पष्ट रूप से संभावित प्रकृति का है, जो पट्टिका जाति के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में अनुसूचित जाति और भेद के रूप में माने जाने के हकदार थे। 'थंडन' जो एझुवा और थियास थे और जो अनुसूचित जाति के थे, के बीच बनाने की मांग की गई थी, जिसे कानून की नजर में अस्वीकार्य और गैर-अनुचित माना गया था। पट्टिका जाति के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून ने कोचीन और मालाबार क्षेत्र के एझुवा और थियास सहित सभी थंडन को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का दावा करने का अधिकार दिया। उस अधिकार को केवल उस प्रभाव के विशिष्ट प्रावधानों या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी रूप से छीना जा सकता हैं। हम संशोधित कानून में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान या इरादा नहीं देखते हैं कि यह माना जाए कि पात्रता को पूर्वव्यापी रूप से छीन लिया गया है ताकि वे लोग भी प्रभावित हों जो पहले से ही अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से लाभान्वित हुए थे। किसी भी दर पर, थंडन के नाम से जाने जाने वाले एझुवा को

जारी किया गया प्रमाणपत्र, जो राज्य के कोचीन और मालाबार क्षेत्र का मूल निवासी था, वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ने थंडन की दो श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं किया। 2007 के संशोधन अधिनियम तक पहली बार इतना अंतर पेश किया गया।

29. इसके अलावा, पट्टिका जाति के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले तक काफी समय तक व्याप्त भ्रम के कारण थंडन के नाम से जाने जाने वाले एझुवास और थियास को बाहर करने का सवाल कानून और समानता अच्छे विवेक के सिद्धांत दोनों में अनुचित होगा। महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद (2001) 1 एस.सी.सी. 4 में, यह न्यायालय कुछ इसी तरह की स्थिति से निपट रहा था। यह एक ऐसा मामला था जहां एक छात्र ने खुद को अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार होने का दावा करके एम.बी.बी.एस. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया था। छात्र ने दावा किया कि हल्बा-कोष्टी संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश में उल्लिखित हल्बा के समान थे। इस न्यायालय ने माना कि न तो सरकार और न ही न्यायालय आदेश में उल्लिखित जातियों की सूची में कुछ जोड़ सकते हैं और हल्बा-कोश्तियों को तर्क या व्याख्या की किसी भी प्रक्रिया द्वारा हल्बा नहीं माना जा सकता है। ऐसा कहने के बाद, जो प्रश्न विचार के लिए आया वह यह था कि क्या आरक्षण का लाभ वापस लिया जा सकता है और उम्मीदवार को उस श्रम से वंचित किया जा सकता है जो उसने

मेडिकल डिग्री प्राप्त करने में किया था। इस न्यायालय ने उनके द्वारा अर्जित योग्यता के ऐसे किसी भी नुकसान की रक्षा करते हुए कहा:

> "इन परिस्थितियों में, यह निर्णय उनके द्वारा प्राप्त की गई डिग्री और एक डॉक्टर के रूप में उनकी प्रैक्टिस को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि वह अनुसूचित जनजाति आदेश के तहत आने वाली अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, वह अनुसूचित जनजाति आदेश का आगे या किसी अन्य संवैधानिक उद्देश्य के लिए लाभ नहीं उठा सकता। (***) हम यह स्पष्ट करते हैं कि जो प्रवेश और नियुक्तियाँ अंतिम हो गई हैं, वे इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगी।

30. कविता सोलुंके बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 8 एससीसी 430, भी एक ऐसा ही मामला था जहां सवाल यह था कि क्या अपीलकर्ता जो 'हल्बा-कोष्टी' था, उसे आरक्षण और रोजगार के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में 'हल्बा' माना जा सकता है। इस न्यायालय ने लंबे समय से चले आ रहे भ्रम के इतिहास का पता लगाया कि क्या 'हल्बा' 'हल्बा-कोष्टी' के समान है और निष्कर्ष निकाला कि 'हल्बा' और 'हल्बा-कोष्टी' को एक ही नहीं माना जा सकता है, सिद्धांत मिलिंद के

मामले में कहा गया है (सुप्रा) 'हल्बा-कोष्टी' को हल्बा अनुसूचित जनजाति मानकर दी गई नियुक्तियों की भी रक्षा करने के लिए आकर्षित था, हालांकि राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति 'हल्बा' का ऐसा विस्तार स्वीकार्य नहीं था। . इस न्यायालय ने कहा:

> "यदि अपीलकर्ता के शिक्षक के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले ही "हल्बा-कोष्टी" को "हल्बा" माना गया है और यदि उसके निष्कासन का एकमात्र कारण मिलिंद मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है, तो इसके खिलाफ सुरक्षा का कोई कारण नहीं है जिन नियुक्तियों के आवेदन अंतिम हो गए थे, उन्हें इस न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कासन अपीलकर्ता पर भी लागू नहीं किया जाना चाहिए। मिलिंद मामले में संविधान पीठ ने उस पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया था जिसमें कई वर्षों से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी और इस तथ्य पर कि लंबे समय तक "कोष्टी" को अनुसूचित जनजाति के रूप में मानते हुए नियुक्तियाँ और प्रवेश किए गए थे और निर्देश दिया था कि ऐसे प्रवेश और नियुक्तियाँ जहाँ कहीं भी समान हों अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया था, इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित नहीं होगा"।

31. संदीप सुभाष पराते बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य , (2006) 7 एस.सी.सी. 501 में, 'हल्बा' और 'हल्बा-कोष्टी' के बीच इसी तरह के भ्रम से निपटते हुए और मिलिंद के मामले (सुप्रा) में अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए यह न्यायालय द्वारा यह माना गया कि जिन अभ्यर्थियों ने अवांछित लाभ प्राप्त किया है, उन्हें बाहर करना केवल तभी उचित होगा, जब न्यायालय को दावा सही लगे। महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय के. निमजे, (2007) 14 एससीसी 481 में इस न्यायालय ने माना कि राहत देना उस व्यक्ति की प्रामाणिकता और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

32. वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रामाणिकता की कमी का कोई सबूत नहीं है। इसलिए, मिलिंद के मामले (सुप्रा) के निर्णय के तहत उपलब्ध सुरक्षा प्रतिवादी को भी स्वीकार्य हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 2007 में प्रदर्शित अभिव्यक्ति 'थंडन' की सच्ची और सही रचना पर भी 'थंडन' के रूप में जाने जाने वाले 'एझुवास' और 'थियास' को शामिल नहीं किया गया है और यह मानते हुए कि दोनों अलग-अलग हैं समय के सभी प्रासंगिक बिंदु, तथ्य यह है कि स्थिति तब तक स्पष्ट नहीं थी जब तक कि 2007 के संशोधन अधिनियम ने दोनों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं कर दिया, जिससे संशोधन अधिनियम लागू होने की तारीख तक राज्य की सेवा के लिए नियुक्त सभी लोग सेवा में बने रहने के हकदार होंगे।

33. केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 5 सितंबर, 2012 के आदेश के खिलाफ दायर 2013 की एसएलपी (सी) संख्या 24775 से उत्पन्न सिविल अपील में, उच्च न्यायालय ने जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। उस अपील में प्रतिवादी के पक्ष में कानूनी रूप से बुरा माना गया क्योंकि जांच समिति ने उस सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया था जिस पर उस मामले में प्रतिवादी ने भरोसा किया था। प्रमाणपत्र की वैधता की कोई जांच नहीं की गई थी और न ही जांच समिति द्वारा पारित आदेश कारणों से समर्थित था। हमारी राय में, उस तर्क में कोई कानूनी दोष नहीं है, यहां तक कि कोई विकृति भी नहीं है जो हमारे हस्तक्षेप की मांग कर सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले पर निष्पक्ष दृष्टिकोण रखता है और किसी भी प्रकार की अवैधता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है।

34. परिणामस्वरूप, ये अपीलें विफल हो जाती हैं और इन्हें खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी वी.के. महानुदेवन को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में 30 अगस्त, 2007 तक दिया गया लाभ अबाधित रहेगा, पदोन्नति या अन्यथा के संदर्भ में कोई भी लाभ जो प्रतिवादी को उक्त तिथि के बाद दिया गया हो। केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में माने जाने के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सलाह दिए जाने पर उसे वापस लिया जा सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि प्रतिवादी-वी.के. महानुदेवन भविष्य में अनुसूचित जाति के

उम्मीदवार के रूप में किसी भी लाभ का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन ओबीसी उम्मीदवार के रूप में उन्हें स्वीकार्य किसी भी लाभ से इनकार नहीं किया जाएगा। पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कोलम मोट्यार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।